सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-31 अंक-12 22 जून, 2016 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ एआईडीएसओ के नेतृत्व में हुए छात्र आन्दोलन की जीत

गुजरात के छात्र आन्दोलन के इतिहास में एआईडीएसओ ने एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज कराई जब उसके लगातार दबाव के चलते गुजरात सरकार को 7 जून 2016 को साईंस स्ट्रीम के 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक समेस्टर प्रणाली हटानी पड़ी। सेमेस्टर प्रणाली के लिए जरूरी बुनियादी ढाँचे के अभाव में ही 2011 में इसके लागू किये जाने के बाद से ही पूरे साल परीक्षाएं चलती रहने की वजह से अध्ययन के कारगर दिन कम हो जाने, अध्यापकों को क्लेरिकल कामों में व्यस्त रहने को मजबूर कर दिये जाने, अध्यापन और गैर अध्यापन स्टाफ की कमी, इन सब ने शिक्षा के स्तर पर भारी प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसके अलावा शिक्षा का खर्च भी बढ़ कर दोगुना हो गया था। छात्र, अभिभावक, यहाँ तक कि अध्यापक और स्कूल-कॉलेजों के प्रिंसीपल शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रणाली का तीखा दंश झेल रहे थे। बिना पढ़ाई परीक्षाओं के बोझ ने छात्रों को आत्महत्या तक भी पहुंचा दिया था। इस पूरे पाँच साल की अवधि के दौरान गुजरात के स्कूल-कॉलेजों और अन्य जगहों पर एआईडीएसओ ने विभिन्न तरह के आन्दोलन संगठित किये। एआईडीएसओ द्वारा विभिन्न दायरों से सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन दिये गये। इसने एक रायशुमारी फार्म तैयार किया जिसे 10,000 से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों और गुजरात के जागरूक नागरिकों ने अपने हस्ताक्षर सहित भरा। राज्य भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित हजारों पोस्ट कार्ड राज्य के शिक्षामंत्री के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री को भेजे गए जिनमें सेमेस्टर प्रणाली हटाने की मांग की गई। सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरने, रैलियाँ, जनसभाएं, विचार गोष्ठियाँ, चर्चाएं, हस्ताक्षर अभियान प्रतीकात्मक भूख हड़ताल आदि सभी कुछ किया गया। ऑल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी की गुजरात इकाई और गुजरात राज्य आचार्य महामण्डल के साथ मिल कर एआईडीएसओ ने अहमदाबाद में एक कन्वेन्शन आयोजित की। छुट्टियों के दौरान भी एआईडीएसओ स्वयंसेवकों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर लेने के लिए गाँवों का भी दौरा किया। आन्दोलन के दबाव ने सरकार को सेमेस्टर प्रणाली वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।

नकली आर्थिक वृद्धि को लेकर पाली गई खुशफहमी

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 189 देशों की एक संस्था है, जिसका कथित मिशन, अन्य बातों के अलावा 'दुनियाभर में उच्च रोजगार को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना' है। लेकिन, असल में, आईएमएफ की भूमिका, अन्य बातों के साथ-साथ, बनावटी प्रस्थापनाओं की भरमार के जरिये संकटग्रस्त प्रतिक्रियावादी मरणासन्न पूंजीवाद का गुणगान करना है। हाल ही में, आईएमएफ द्वारा जारी किये गये विश्व आर्थिक नजरिये में कहा गया है कि धूमिल वैश्विक आर्थिक भविष्यवाणी के बावजूद भारत 2016-17 की वृद्धि दर (मतलब जीडीपी)7.5% के साथ जो कि चीन से ज्यादा है, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के तौर पर एक चमकता स्थान बना रहा है। इसने यह आशावाद व्यक्त किया है कि "भारत की वृद्धि-विकास प्राइवेट उपभोग से संचालित होकर जारी रहेगी। जिसे ऊर्जा के दामों के घटने और वास्तविक आमदनी बढ़ने से फायदा पहुंचा है।" आईएमएफ की इस रिपोर्ट के एकबार प्रकाशित होते ही भारत सरकार और स्तम्भकार-अर्थशास्त्रियों को शासक पूंजीवाद की अपनी ताबेदारी में खुशफहमी हो गई है और ऐसी 'शानदार' वृद्धि के लिए एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि यह किसकी वृद्धि है, किसका विकास है? क्या यह देश की जनता का विकास है या मेहनतकश लोगों के खून का आखरी कतरा तक निचोड़ने वाले मुट्ठीभर उद्योगपतियों-एकाधिकारी पूंजीपतियों का?

कोई भी समझदार आदमी इस बात से सहमत होगा कि आर्थिक विकास या वृद्धि को आम आदमी के जीवन स्तर के उत्थान, उद्योग और कृषि दोनों के तेजी से चौतरफा विकास, जनता की क्रय शक्ति में उछाल, बेरोजगारी में गिरावट और देशवासियों के लिए सभी आवश्यक चीजों और सेवाओं की उपलब्धता से जाँचा जा सकता है। लेकिन इस मामले में देश का आलम क्या है?

विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि "उच्चतर आर्थिक विकास-वृद्धि का प्रतिफलन उच्चतर खाद्य उपभोग में पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुल मिलाकर अच्छी खुराक की तो बात छोड़ ही दीजिए, इससे पता चलता है कि गरीब और भूखे लोगं कुल मिलाकर हुई इस वृद्धि से ज्यादा फायदा उठाने में विफल रहे हैं। तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। एक वैश्विक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि दुनिया में प्रत्येक को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य है। अगर सम्पूर्ण वैश्विक खाद्य आपूर्ति का बराबर बंटवारा कर दिया जाये और पैदा की गयी सारी खाद्य सामग्री को बराबर-बराबर हिस्सों में बांट दिया जाये-तो खाना हर एक के लिए प्रचुर मात्रा में होगा, बल्कि कुछ बच जायेगा; दरअसल, आज दुनिया में हर एक को खाना खिलाने के लिए जितनी खाद्य सामग्री की जरूरत है उससे 10 प्रतिशत ज्यादा उगता है। लेकिन दुनियाभर में उगाये गये 1.2 से लेकर 2 बिलियन टन खाद्य का 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक कभी उनकी थाली में नहीं पहुँच पाता है और बर्बाद हो जाता है। भारत इसका आँखें खोल देने वाला उदाहरण है। यह सबसे बड़ी कुपोषित और भूखी आबादी का घर है जिसमें 230 मिलियन लोग रोजाना भूखे सोते हैं। लगभग 165 मिलियन बच्चे कुपोषण और संक्रमण के फलस्वरूप नाटे रह जाते हैं, शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर छोड़ दिये जाते हैं। एक बच्चे की उसकी स्वस्थ बढ़ोतरी के लिए जरूरी सभी विटामिन और न्यूटरियंट (पोषक तत्व) प्रदान करने के लिए रोजाना महज 16 रुपये खर्चा आता है। लेकिन घोर गरीबी माँ-बाप को उस सबका प्रबंध करने से वंचित कर देती हैं जो उनके बच्चों के लिए एकदम न्यूनतम है। बाल चिकित्सा की भारतीय अकादमी के मुताबिक घोर कुपोषण की वजह से भारत में आधा मिलियन (5 लाख) बच्चे अपने 5वें जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। हर एक मिनट में एक बच्चा मर जाता है। पिछले 20 वर्षों में लगभग 3 लाख किसानों ने गरीबी की दुर्दशा सहन नहीं कर पाने से आत्महत्या कर ली। भारत में हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर लेता है। 'आगे बढ़ रहे' भारत का 33 प्रतिशत हिस्सा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कांग्रेस-बीजेपी गठजोड़ों का वामपंथी विकल्प तैयार करने के लिए विशाल संयुक्त रैली

बैंगलोर (कर्नाटक) : 6 जून को कर्नाटक के बैंगलोर शहर में रेलवे स्टेशन से फ्रिडम पार्क तक वामपंथी दलों के संयुक्त जुलूस ने लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लिया। यह जुलूस राज्य में कांग्रेस और केन्द्र में बीजेपी सरकार के कुशासन के खिलाफ आयोजित किया गया था। हजारों मजदूर, किसान, आंगनवाड़ी कर्मी, आशा कर्मी, ठेके के मजदूर-कर्मचारी, शिक्षक-प्रोफेसर, छात्र-नौजवान और महिलाएं इस जुलूस में शामिल थे। इस जुलूस ने वाम विकल्प की आवाज बुलंद करते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस-बीजेपी से कुछ नहीं होगा – चाहिए बुर्जुआ शोषणमूलक व्यवस्था के विकल्प की सोच, वैकल्पिक नीति। इसमें मौजूद थे सीपीआई(एम), सीपीआई, एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), सीपीआई(एमएल)-लिबरेशन और ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक के कार्यकर्ता-समर्थक। जुलूस पार्क में पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। सभा में वामपंथी दलों के केन्द्रीय नेतृत्व ने अतिथि वक्ता के तौर पर भाषण दिये।

फ्रिडम पार्क में हुई जनसभा में सीपीआई(एम) के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी ने उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस और केन्द्र में बीजेपी

(शेष पृष्ठ 8 पर)

बैंगलोर में संयुक्त रैली को सम्बोधित करते हुए कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती

नकली आर्थिक वृद्धि...

(पृष्ठ 1 का शेष)

इस साल भयंकर सूखे की चपेट में आ गया था। पिछले साल हर किसी ने देखा कि देश के विभिन्न हिस्सों में मुसलाधार बारिश, अति वृष्टि और बाढ़ के प्रकोप ने कितनी भारी मुसीबत पैदा कर दी थी। 'आगे बढ़ रहे' भारत के शासकों और उनके ताबेदारों को जो अन्तरिक्ष में उपग्रह भेजने में व्यस्त हैं या सफलतापूर्वक उच्च शक्ति वाली मिसाइलें दागने पर इतरा रहे हैं, बाढ़ या सूखे के रह-रह कर आने वाले इस प्रहार के शिकार बनने वाले असहाय लोगों की जरा भी चिन्ता-फिक्र नहीं है। उनके लिए, तो इसकी बजाय तात्कालिक काम है "भारत माता की जय" का जाप करवाना सुनिश्चित करना, या अयोध्या में राम मन्दिर बनाना या मेडम टयूसाउड्स म्युजियम में प्रधानमंत्री की मोम की मूर्ति लगवाना। दूसरा झांसा है लोगों की 'उच्चतर आय' की झूठी कहानी। गरीबी की सीमा ही मानती है कि कंगाली के मारे हुए लोगों की आय कितनी तेजी से गिर रही है जिसके फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति घटती जा रही है। इसी का नतीजा है कभी न खत्म होने वाली मंदी और बाजार संकट। हाल ही में प्रकाशित सामाजिक-आर्थिक जन गणना रिपोर्ट ने उजागर किया था कि 75 प्रतिशत ग्रामीण परिवार महीने में 5000 रुपये भी नहीं कमाते हैं। 92 प्रतिशत परिवारों में मुख्य कमाई कर्ता व्यक्ति 10 हजार रुपये प्रति महीना से भी कम कमाता है। कुल ग्रामीण परिवारों में से लगभग 75 प्रतिशत परिवारों में सबसे ज्यादा कमा कर लाने वाले व्यक्ति की महीने भर की कमाई 5000 रुपये या इससे भी कम है। यह 1000 रुपये भी हो सकती है या फिर 10 रुपये तक भी। साफ जाहिर है कि उनको घोर गरीब का दर्जा दिया जा सकता है। 6 लाख 68 हजार परिवार भीख मांग कर जिन्दा हैं जबकि 4 लाख 8 हजार परिवार रद्दी चुग कर अपना गुजर-बसर करते हैं। दिवंगत अर्जुन सेनगुप्त जो एक दशक पहले असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष रहे, का अन्दाजा था कि अगर गरीबी का हिसाब-किताब करने के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च करने की हैसियत का मापदण्ड इस्तेमाल किया जाये तो भारत की 77 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। भारत सरकार और इसकी जी-हुजूरी करने वाले विशेषज्ञों की तरफ से गरीबी रेखा तय करने के लिए वैकल्पिक अवास्तविक मापदण्ड खोजने सहित ढेर सारी तकनीकों और हथकण्डों के जरियें गरीबी के आँकड़ों को बनावटी तौर पर कम करके दिखाने के जी-तोड़ प्रयास किये जाते रहे हैं। फिर भी पूँजीवादी भारत में लोगों की बढ़ती गरीबी को ढका या छुपाया नहीं जा सका। सभी हेरा-फेरियों और सांख्यिकीय बाजीगरी के बाद भी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पास करते हुए योजना आयोग ने 2013 में अंदाजा लगाया था कि सब्सिडी पर दिये जाने वाले अनाज का अधिकार 67 प्रतिशत बीपीएल आबादी को कवर कर लेगा। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति ने भी पिछले साल अपने भाषण में इस आँकड़े का अनुमोदन किया था। बढ़ती गरीबी और भूख गिरती हुई आमदनी की तसदीक करती है। इसलिए "वृद्धि प्राइवेट उपभोग से संचालित होकर जारी रहेगी" का दावा अगर सफेद झूठ न भी हो तो खोखला जरूर है। सर्वोपरि, भारत रोजगार हानि पर कोई अधिकृत आँकड़े प्रकाशित नहीं करता, जाहिर है कि इसका कारण सच्चाई को छुपाना है। लेकिन गैर सरकारी स्रोतों और मीडिया की रिपोर्टों से पता चलता है कि 18-25 वर्ष की आयु ग्रुप के नौजवानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्किल्ड या दक्ष होते हुए भी उनमें बेरोजगारी 32 प्रतिशत है। हाल ही में छपी इस खबर से शिक्षितों में बेरोजगारी का आलम क्या है यह जाना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चपरासी के 369 पदों की नौकरी चाहने वाले 23 लाख नौजवानों ने आवेदन फार्म भरे थे जिनमें 255 पीएचडी, 24,969 स्नातकोत्तर और 1 लाख 50 हजार से ज्यादा स्नातक शामिल थे। बढ़ती ग्रामीण गरीबी इस बात की सूचक है कि ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है। ग्रामीण इलाके में छिपी हुई बेरोजगारी का एक रुझान पाया जाता है। (छिपे हुए बेरोजगार वे हैं जो अपने हाल पर काम करते हैं और जिन साधनों से वे काम करते हैं उनकी बनिस्बत उनकी संख्या अत्यधिक है। उनमें से एक संख्या में लोगों को उस काम से निकाल कर अर्थव्यवस्था के किसी दूसरे क्षेत्र के काम में लगा देने से, जिस क्षेत्र से वे वापस लिए गये उस क्षेत्र का कुल आउटपुट कम नहीं होगा जबकि इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण पुनर्गठन भी नहीं करना होगा। ग्रामीण भारत में छिपी हुई बेरोजगारी 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत है। पूँजीवाद के घनघोर असमाधेय बाजार संकट की वजह से मौजूदा लगे हुए उद्योगों में तालाबन्दी के चलते रोजगार हानि की बढ़ती संख्या बेरोजगारों की संख्या को ज्यादा बढ़ा रही है।

दूसरा बिन्दु है "घटती उर्जा कीमतों और बढ़ती वास्तविक आयों से लोगों को फायदा होने" के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) की टिप्पणी, यह भी तथ्यों की घोर गलत प्रस्तुति है। भारत में कच्चे तेल की कीमतें 11 साल के दौरान सबसे निचले स्तर 37.34 डॉलर प्रति बैरल पर ठहरी हुई हैं। तेल मंत्रालय के मुताबिक देश सिर्फ वित्त वर्ष 2016 में अपने तेल आयात बिल पर (पिछले अनुमान 1.5 लाख के मुकाबले) 2.14 लाख करोड़ रुपये बचाने पर आमादा है। यह पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती के रूप में सरकार को होने वाले फायदे के अलावा है। सरकार ने वर्ष 2014-15 में पेट्रोलियम क्षेत्र से उत्पादन शुल्क वसूली में 99,184 करोड़ रुपये बटोरे थे। चालू वित्त वर्ष के बजट में आवश्यक तौर पर रसोई गैस और मिट्टी के तेल के लिए 2014-15 के लिए दी गई 60,270 करोड़ रुपये की सब्सिडी के मुकाबले महज 30,000 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई है। इससे सरकार के अलावा और जिनको बड़ा फायदा हुआ है उनमें हैं तेल की बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ। उदाहरण के लिए मुकेश अम्बानी की कम्पनी रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का मुनाफा 2015-2016 की चौथी तिमाही में लगभग 16 प्रतिशत बढ़कर 7,398 करोड़ रुपये(1.1 बिलियन डालर) हुआ है। यह पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है। इसके रिफाइनिंग और पेट्रो कैमिकल के कारोबार में जबरदस्त मार्जिन की वजह से ऐसा हुआ है लेकिन जनसाधारण, इसके विपरीत बाजार-अर्थव्यवस्था के पैरोकारों ने पेट्रोल-डीजल के खुदरा दामों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करते समय जो वायदा किया था, उनको अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने का फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उससे उनको वंचित कर दिया। लोगों को राहत प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों और कारपोरेट सैक्टर को लाखों करोड़ रुपये की टैक्स माफी और टैक्सों में छूट की सौगात देने से हुए भारी बजट घाटे को पूरा करने के लिए नाजायज तौर पर ईंधन पर बार-बार अतिरिक्त शुल्क, सैस लगाकर सरकार ने सारा फायदा खुद हड़प लिया। जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 367 प्रतिशत नीचे आ गये हैं, उससे मेल खाती हुई तेल के खुदरा दामों में गिरावट आने की बजाय, केवल नाममात्र की 16 प्रतिशत ही गिरावट आई। वर्तमान में पैट्रोल व डीजल के खुदरा दामों में टैक्सों का हिस्सा लगभग क्रमशः 57 प्रतिशत और 55 प्रतिशत है जो तेल के खुदरा दामों को तेल के अन्तर्राष्ट्रीय खुदरा दामों से वस्तुतः दुगुना कर देता है। इसलिए आईएमएफ का यह दावा कि 'तेल ने खाद्य सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने में भारत की मदद की है' एक बहुत बड़ी झूठ है बल्कि मामला ठीक इसके उलट है। अन्तर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के साथ-साथ खाद्य सामग्रियों की कीमतें घटने की बजाय उनमें उछाल आया हुआ है।

अन्ततः सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि और इसकी गणना पद्धति, हिसाब-किताब लगाने के आधार को लेकर भी एक बात कहनी है। जैसे कि हमने अपने पूववर्ती लेखों में बार-बार दिखाया है जीडीपी बढ़ने पर जश्न मनाना बेमायने है क्योंकि जीडीपी पैदा हुई धन-दौलत के बंटवारे की सूचक नहीं है। इसके अलावा, हाल ही में, जीडीपी की गणना करने के तरीके में इतनी फेरबदल की गई है कि 4.7 प्रतिशत वृद्धि का आंकड़ा छलांग लगाकर 6.9 प्रतिशत हो गया है। यह चालबाजी यह शेखी बघारने में काम आयी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से आगे निकल गई है। पूँजीवादी भारत में, किसी अन्य पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देश की तरह, चंद अमीरों और विशाल संख्यक गरीबों के बीच की खाई सूरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 प्रतिशत अमीर लगातार अमीर से और भी अमीर होते जा रहे हैं, गरीबों के पास जितनी धन-दौलत है उससे 370 गुना ज्यादा इनके पास है। भारत की कुल आबादी का 1 प्रतिशत बनने वाले सुपर अमीर तो और भी तेजी से अमीर बनते जा रहे हैं। नाइट फ्रेंक इण्डिया में शोध और सलाहकार सेवाओं के डायरेक्टर और मुख्य अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2003 से 2013 के बीच के दशक में भारत में अरबपतियों की संख्या 23 से बढ़कर 60 हो गई, इसमें 161 प्रतिशत उछाल आया है और अति ऊंचे नेट व्यक्तियों की संख्या 164 प्रतिशत बढ़कर 598 से बढ़कर 1576 हो गई है। यह साफ दर्शाता है कि न्यायसंगतता के नजरिये से, जबरदस्त असमानता बढ़ती जा रही है, चाहे आर्थिक वृद्धि-विकास पर कितनी ही खुशी मनाई जा रही हो, उनके गुर्गे अर्थशास्त्रियों और स्तम्भकार भारत के बारे में "विश्व अर्थव्यवस्था में चमकते स्थान" सम्बन्धी आईएमएफ के वर्णन पर सरकार की प्रफुल्लता का समर्थन करने लायक न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर रघुराम राजन ने कहा था कि यह अन्धों में काना राजा जैसा मामला है। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तमगे के बारे 'खुशफहमी' पालने के बारे में आगाह करते हुए उन्होंने दिखाया कि हर एक भारतीय को एक अच्छी आजीविका प्रदान करने के लिए हमें अभी मीलों दूर जाना है। उद्योगों में लगी हुई क्षमता का 30 प्रतिशत इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है – यह कहते हुए उन्होंने औद्योगिक उत्पादन में मन्दी की पुष्टी भी की है। लेकिन जो तथ्य दबा कर रख लिया वह यह कि मरणासन्न पूँजीवाद में इस परिदृश्य में कोई बदलाव नहीं हो सकता। उल्टे, वक्त गुजरने के साथ-साथ जनसाधारण के लिए हालात और भी बुरे सपने जैसे हो जायेंगे और उनकी बलि चढ़ाकर अमीर खुशहाल होते जायेंगे।

आरोन में लगाया बच्चों का समर कैम्प

बच्चों में सृजनशीलता विकसित करने के लिए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों में समर कैम्प लगाये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आरोन में द्वारानगर में अभिव्यक्ति मंच और आर्ट एज के संयुक्त तत्वावधान में एक ऐसा ही कैम्प लगाया गया। इस पांच दिवसीय कैम्प में 200 बच्चों ने शिरकत की। उन्हें नाटक, संगीत, डांस, चित्रकारी, मार्शल आर्ट आदि सिखलाई गई। मुख्य वक्ता कॉ. लोकेश शर्मा थे और संचालन कॉ. मनीष श्रीवास्तव ने किया।

मजदूर आन्दोलन में क्रान्तिकारी दृष्टिकोण क्या हो – शिवदास घोष

(17 और 18 मार्च 1974 को पश्चिम बंगाल के इस्पात नगर दुर्गापुर में दुर्गापुर स्टील वर्कर्स को-अर्डिनेशन कमेटी के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित अखिल भारतीय यू.टी.यू.सी. के अध्यक्ष, इस युग के महान मार्क्सवादी दार्शनिक, चिंतक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया के संस्थापक महासचिव, हमारे नेता, शिक्षक तथा पथ-प्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष ने जो भाषण दिया था वह भारत के मजदूर आन्दोलन की मौजूदा समस्याओं को समझने में और उनके समाधान के लिए मजदूर आन्दोलन में लगे क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं की आचरण-विधि और दृष्टिकोण के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। कॉ. घोष का यह भाषण 'श्रमिक आन्दोलन में क्रान्तिकारी दृष्टिकोण क्या हो' नामक पुस्तक में छपा है। कॉमरेड घोष के उक्त भाषण को पुन:प्रकाशित कर रहे हैं।)

दुर्गापुर स्टील वर्कर्स की इस जनसभा में भारत की मौजूदा राजनैतिक परिस्थिति एवं इस स्थिति में मजदूर और आम लोगों को क्या करना चाहिये, इस पर चर्चा करने के लिए मुझे आग्रह किया गया है – इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह कि एक बात सभी महसूस कर रहे हैं, चाहे अनुभव जैसा भी क्यों न हो, हर किसी को एक बात सोचनी पड़ रही है कि चारों ओर से देश की हालत में इस तरह कि गिरावट क्यों हो रही है? जो बात कॉमरेड सुबोध बनर्जी, मुख्य अतिथि ने कही कि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और विशेष रूप से राष्ट्र के नैतिक पहलू की ओर अगर हम गौर करें तो देखेंगे कि स्थिति सचमुच ही भयानक हो गई है। मैं एक बात बिना कहे नहीं रह पा रहा हूँ कि खाली पेट, अधनंगी-अधभुखी हालत में रहते हुए भी, शोषण-अत्याचार से जर्जरित होते हुए भी, एक राष्ट्र उठ खड़ा हो सकता है यदि उस राष्ट्र का नैतिक बल अटूट रहे और जन साधारण के सामने एक सही आदर्श रहे। वियतनाम को देखिये, चीन की क्रान्ति का इतिहास पढ़िये। क्रान्ति के पहले चीन के आम लोगों की आर्थिक दुर्दशा, अत्याचार, शोषण किस चरम सीमा पर जा पहुँचा था उसे याद कीजिये। फिर भी उन देशों के लोग, वहाँ की जनशक्ति उठ खड़ी हो सकी। एक ही चीज के आधार पर यह संभव हो सका। वह यह कि इतने अत्याचार और लांछना के बावजूद जनता के चरित्र में, समाज में थोड़ा-बहुत नैतिक बल, पुरानी नीति- नैतिकता के आधार पर ही सही, बचा हुआ था तथा जन-साधारण सही क्रान्तिकारी आदर्श अपनाने एवं उसके अनुसार संग्राम के लिए उपयोगी नया नैतिक बल पैदा करने में सक्षम हो सके थे। तभी वियतनाम की जनता को बम से भी बर्बाद नहीं किया जा सका। सारे देश को रेगिस्तान बना देने के बाद भी, उस देश के निराहार, भूखे, अशिक्षित किसान एवं जन-साधारण के मस्तक को झुकाया नहीं जा सका। बारह-तेरह वर्ष के किशोर-किशोरियों से लेकर वृद्ध-वृद्धाओं तक सभी कोई मौत की परवाह न कर लड़ने की यह दृढ़ता कहाँ से पाये? क्या वे सभी लेनिन-स्तालिन हैं? क्या वे क्रान्ति के सारे सिद्धान्तों को बखूबी समझ गये थे? यह तो बिलकुल निराधार बात होगी। किन्तु एक चीज उनके पास थी और है, वह है उनका नैतिक बल व चरित्र जिनके आधार पर वे हर तरह के शोषण के खिलाफ असीम हिम्मत के साथ खड़े हो सके थे।

भारतवर्ष का शासक-वर्ग राष्ट्र के इसी नैतिक बल व चरित्र को पूरी तरह बर्बाद कर देने की साजिश में लगा हुआ है। वे लोग धुरंधर हैं। वे जानते हैं कि हजार अत्याचार, दमन, उत्पीड़न चलाकर भूखा रख कर भी किसी राष्ट्र को, किसी देश की जनता को, महज पुलिस फौज की ताकत से ज्यादा दिनों तक दबा कर रखा नहीं जा सकता। सभी युगों के स्वेच्छाचारी शासकों के अत्याचार का इतिहास यह बताता है कि शोषण व दमन के जरिये आखिर तक जनशक्ति को दबाया नहीं जा सकता; सत्ता पर कब्जा जमाये नहीं रखा जा सकता। जनशक्ति सिर ऊँचा कर उठ खड़ी होगी ही, यदि उसे सही क्रान्तिकारी आदर्श प्राप्त हो जाए और उसका नैतिक बल अटूट हो।

भारत के बुर्जुआ वर्ग, शासक वर्ग के लोगों ने इतिहास से अच्छी सीखें नहीं ली। लेकिन शैतान-शासक के नाते उन्हें जो शिक्षा लेनी थी अपने हित में उस सीख को उन्होंने ठीक से चुन लिया है। वह यह कि देश के नैतिक बल को खत्म कर दो, लोगों के चरित्र को बर्बाद कर दो। तब वे खाना न मिलने पर, सैकड़ों अत्याचारों के बावजूद कुत्तों की तरह गुर्राते रहेंगे, कभी-कभी गुस्सा भी जाहिर करेंगे, शायद छिटपुट विद्रोह भी करेंगे, लेकिन संगठित क्रान्तिकारी आन्दोलन को जन्म नहीं दे पायेंगे, क्योंकि क्रान्तिकारी आदर्श अपनाने एवं क्रान्ति संगठित करने के लिए सही मूल राजनैतिक लाइन (correct base political line) और सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के अलावा भी जो चीज अपरिहार्य है, वह है नैतिक बल। व्यवहारिक राजनीति (Practical politics) की दुहाई दे कर संकीर्ण दलीय स्वार्थ के लिए इन्सान में नीच प्रवृत्तियों को बढ़ाने की यह घिनौनी साजिश उन्होंने रची है।

अतएव आप जो यह सांस्कृतिक पतन देख रहे हैं, यह आकस्मिक (accident) नहीं है। कोई स्वत:स्फूर्त चीज नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है कि यह कोई पहले से निश्चित घटना है, मानो ऐसा ही होना था और हो रहा। हालाँकि, यह घटना लोगों की नजर से बच कर घट रही है मगर असलियत में इसके पीछे शासक वर्ग की योजना और वरद हस्त है।

मुँह से तो वे तमाम लोगों को ईमानदार बनने, अच्छा बनने कि सलाह दे रहे हैं, परन्तु व्यवहारिक राजनीति की दुहाई देकर संकीर्ण पार्टी स्वार्थ की तात्कालिक जरूरतों को सामने रखते हुये शासक पार्टी ही नहीं बल्कि क्रान्ति का बिल्ला लगाये अनेक पार्टियाँ भी इन्सान के अंदर जितनी सारी नीच प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। कायर की तरह आक्रमण करने की प्रवृत्ति को, दस लोग मिलकर एक को मारने के हीन कार्यकलाप को, सैद्धान्तिक चर्चा और तर्क-विचार के बदले असहिष्णुता आदि को संग्राम और लड़ाई के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है। लोभ, लालच और नीचता जो किसी इन्सान को हैवान बना देती है, उसकी वीरता एवं सही मर्यादाबोध को नष्ट कर देती हैं – उन्हें आज बढ़ावा दिया जा रहा है। रुपये देकर कार्यकर्ताओं से पार्टी या यूनियन के नियमित कार्य कराये जा रहे हैं। ये सभी व्यवहारिक राजनीति की दुहाई देकर ही किये जा रहे हैं। लाखों बेकारों से आज सारा देश भर गया है। लोगों का पेट नहीं भर रहा है। इस मौके से फायदा उठाकर ये राजनैतिक पार्टियाँ उनका इस्तेमाल कर रही हैं, तथाकथित नौकरी में लगा रहे हैं। आप जानते हैं सभी मनुष्य गुण-दोषयुक्त होते हैं। इंसान के अंदर जो तमाम अच्छे पहलू हैं यानी साहस, वीरता, सहानुभूति, उदारता और कर्त्तव्यबोध के जो पहलु हैं सिर्फ इन को बढ़ाने में मदद करके ही उसके दोष को दूर किया जा सकता है। महज 'दोष दूर करो!' –कहने से ही वह दूर नहीं हो जाता। 'ईमानदार बनो!' 'अच्छे बनो!' के ये उपदेश और दूसरी ओर व्यवहारिक राजनीति की दुहाई देकर जो लोग या पार्टी किसी भी लफ्फाजी की आड़ में–इन्सान के अंदर नीच प्रवृत्तियों को उकसाते हैं वे इसके जरिये जाने-अनजाने पूरे देश के सांस्कृतिक वातावरण, राष्ट्र के नैतिक चरित्र को ही मिट्टी में मिलाने के बुर्जुआ षड्यंत्र को सफल होने में मदद कर रहे हैं। वे व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं या बेईमान यह उतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है।

लुम्पेन व भिखारी किसी देश में क्रान्ति नहीं करते, राजनीति के आधार पर सचेत संगठित शोषित जनता ही क्रान्ति की संगठन शक्ति है

अगर हालत ऐसे ही रहे तो राष्ट्र की नैतिकता तो मिटेगी ही। नैतिकता को अलग रखकर क्रान्ति नहीं होती। जो लोग यह सोचते हैं कि जनता की आर्थिक दुर्गति, उन पर होने वाले जुल्म व उत्पीड़न बढ़ने से खुद-ब-खुद क्रान्ति हो जायेगी, मैं कहूँगा, वे मूर्ख हैं। वे नहीं जानते कि कभी भी देश में भिखारी लोग क्रान्ति नहीं करते, क्रान्ति करते हैं शोषित जनसाधारण। इस बात का एक तात्पर्य है। लुम्पेन लोग (जिनका चरित्र बर्बाद हो गया है) क्रान्ति नहीं करते वरन् सभी देशों में लुम्पेन लोग बुर्जुआ वर्ग के हाथों में, फासिस्टों के हाथों में क्रान्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया की फौज के तौर पर इस्तेमाल होते रहते हैं। इसलिए मार्क्स से लेकर लेनिन, माओ-त्से-तुंग तक सभी का यह कहना था कि आर्थिक दुर्गति के कारण सर्वहारा के भीतर जो लोग 'लुम्पेन' बनते जा रहे हैं, वे हमारे कोई नहीं हैं, क्रान्तिकारी सर्वहारा नहीं हैं। इसलिए क्रान्तिकारी सर्वहारा को क्रान्ति के हित में इस 'लुम्पेनगिरी' (Lumpenism) के खिलाफ लड़ना पड़ता है। महज अभाव से ही विस्फोट की तरह क्रांति नहीं हो जाती। विस्फोट-सा जो होता है वह है विक्षोभ। इसके जरिये आखिरकार शोषकों को ही ज्यादा फायदा होता है। मार्ग गलत, नेतृत्व गलत, सिद्धान्त गलत, क्रांति के सम्बन्ध में स्वच्छ व सही राजनैतिक दृष्टिकोण है नहीं – ऐसे असंगठित जनसाधारण की लड़ाई जब संगठित राजसत्ता के दमन के सामने हार खाती है तब पराजय की मानसिकता छा जाती है। मनुष्य के भीतर संघर्ष की जो मानसिकता थी वह इस तरह खत्म हो जाने से निराशा से पराजय की मानसिकता, चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही जन-आन्दोलन को ग्रसित कर लेती है। फलस्वरूप शोषक वर्ग को सबसे अधिक सुविधा हो जाती है। ऐसे मौके से फायदा उठाकर शोषक वर्ग अपना काम बना लेता है। अपनी शासन-व्यवस्था तथा राजनैतिक संगठन को और थोड़ा मजबूत कर लेता है।

हमारे देश के इतिहास को जरा याद करेंगे तो देखेंगे कि इस देश में बार-बार लड़ाई हुई है। यह कोई नहीं कह सकेगा कि इस देश के युवक, मजदूर, मेहनती जनसाधारण लड़ाई के लिये मैदान में नहीं उतरा, जेल जाने से डरा, कुर्बानी देने से कतराया, प्राणों की आहुति देने से भागा है। इतिहास की जानकारी रखने वाले यह जानते हैं कि इस देश के लोग लड़ने के लिए बार-बार बारूद की तरह विस्फोटित हुए हैं। आजादी हासिल होने के बाद भी पिछले सत्ताइस साल के अंदर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में आत्मत्याग, रक्तपात की कितनी घटनायें हुई, मजदूर, किसान, छात्र-नौजवानों ने कितने ही प्राणों की आहुति दी है। क्रान्ति के लिए प्रबल आकांक्षा लिए इस देश के लोग बार-बार आन्दोलन में आये, प्राण दिये, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? सभी आज कहते हैं कि प्रतिक्रिया की ताकत मजबूत हुई है। जनवादी आन्दोलन पर चोट की जा रही है। फासीवादी हमले हो रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है? जनवादी आन्दोलन को तो अब तक पूँजीवाद को खत्म कर फतह का झण्डा फहरा देना चाहिए था। क्योंकि जनता ने तो क्रान्ति के लिए आवश्यक जनसमर्थन दिया ही था। नेताओं की आवाज पर हजारों-हजार नौजवान क्रान्ति की आशा से आन्दोलन में कूद पड़े थे। फिर भी प्रतिक्रिया ताकतवर क्यों हो गई? क्रान्ति को ही तो ताकतवर होना चाहिये था। क्या यह सब ईश्वर ने कर दिया? या क्या सब माया है? अथवा तंत्र-मंत्र है? जादू-मंतर शायद उनके लिए हो जो विश्वास

(शेष पृष्ठ 4 पर)

मजदूर आन्दोलन में...

(पृष्ठ 3 का शेष)

करते हैं। लेकिन यदि आपके ख्याल से इसमें जादू-मंतर की बात कुछ नहीं हो, अल्ला या ईश्वर की मर्जी जैसी कोई बात भी नहीं हो तो फिर यह सब कैसे हो रहा है? यही है असल सवाल।

केवल आर्थिक मांगें हासिल करना नहीं-बल्कि मजदूरों के अंदर सही क्रान्तिकारी राजनैतिक शक्ति को जन्म देना ही क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन संगठनों का मुख्य कर्त्तव्य है

यहाँ मैं पहले ही आप लोगों को लेनिन के एक कथन की याद करा दूँ। लेनिन ने मजदूरों को बार-बार चेतावनी दी थी। मार्क्स से लेकर हर किसी ने बार-बार इस महत्वपूर्ण बात को दोहराया था। उन सभी ने कहा था कि मजदूर केवल आर्थिक और जनवादी मागों को लेकर कितने ही जुझारू संघर्ष क्यों न करें, जी-जान से लड़ कर वे अपनी मांगें व जनवादी अधिकार कितने ही क्यों न हासिल कर लें, उससे उनकी गुलामी का खात्मा नहीं होता। वे पहले जैसे ही गुलाम रह जाते हैं, जिस अंधकार में थे उसी में रह जाते हैं। महज आर्थिक व जनवादी मांगें लेकर लड़ने से और उसके साथ 'मार्क्सवाद जिन्दाबाद','पूँजीवाद हो बर्बाद' या 'इंकलाब जिन्दाबाद' आदि नारे जोड़ देने से ही उनकी हालत बदल नहीं जाती है। यदि उनकी लड़ाई केवल जनवादी अधिकारों के विस्तार तक (extension of Democratic Rights) के लिए ही हो तो फिर कितने ही जनवादी अधिकार क्यों न अर्जित हों, उससे मजदूरों की मुक्ति (Emancipation) कतई नही हो सकती। इसके लिए मजदूरों को समझना होगा कि जनवादी और आर्थिक मांगों के आधार पर गठित उनके ये संघर्ष अत्याचार के खिलाफ केवल न्यूनतम अधिकारों को लेकर जिंदा रहने के संघर्ष से अधिक कुछ नहीं है। इस तरह रोजमर्रे की मांगों की लड़ाई के जरिये इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने लायक पर्याप्त राजनैतिक शक्ति को जन्म देने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। केवल इन आन्दोलनों के जरिये मजदूरों के भीतर धीरे-धीरे उनकी निजी राजनैतिक शक्ति (संघर्ष कमेटियों) को जन्म दे पाने से ही पूँजीवाद को ध्वस्त करने लायक दीर्घस्थायी लड़ाई(Protracted war)या क्रान्तिकारी लड़ाई करना संभव होगा। यह दीर्घस्थायी लड़ाई राजसत्ता के हजारों दमन-उत्पीड़नों के सामने भी नहीं टूटेगी। जैसे नेपाम बम गिरा कर पूरे देश को रेगिस्तान बना देने पर भी वियतनाम के लोगों की लड़ाई को खत्म नहीं किया जा सका। आखिरकार अमेरिका को सर झुका कर हट जाना पड़ा।

इसलिये ट्रेड यूनियन आन्दोलन के बारे में मार्क्स ने पहले ही आगाह कर दिया था। आखिर मजदूर क्यों ट्रेड यूनियन करेंगे? वे इस वजह से ट्रेड यूनियन करेंगे की यह साम्यवादी शिक्षा लेने का स्कूल है। साम्यवाद के बारे में ज्ञान की शुरूआत यहीं से होती है। सब मिलकर एकजुट होकर प्रतिदिन के अन्याय-अत्याचार के खिलाफ इसी मंच से लड़ते हुए मजदूर घटनाओं के विश्लेषण का, सच की खोज का मौका पाते हैं। वे समझने लगते हैं कि क्रान्ति के बिना मुक्ति क्यों नहीं हो सकती। सच्चे क्रान्तिकारियों के सिवा दूसरा कोई भी रोजमर्रे की लड़ाई के जरिये मजदूरों को इस तरह से शिक्षित नहीं करना चाहता। दूसरे झूठे क्रान्तिकारी मजदूरों से कहते हैं 'यूनियन करो', 'यूनियन चलाओ' और वे खुद ही यूनियन में नौकरशाही को जन्म देने लगते हैं। इस तरह ट्रेड यूनियन आन्दोलन नौकरशाही में बदल जाता है। नेता लोग इस धारणा को पनपाते हैं कि वे सभी महान व्यक्ति हैं। उनकी बात खास महत्व रखती है। मालिक लोग उनसे डरते हैं, उनकी खातिरदारी भी करते हैं। आप लोग याद रखियेगा यह खातिर और डर फुफेरे-मौसेरे भाई हैं। इन सब नेताओं को ये दोनों ही चाहियें। भीतर से वे चाहते हैं कि मालिक लोग उनकी खातिरदारी करें, इसलिये वे मालिकों को डर दिखाते हैं।

मजदूर भी उन सब नेताओं के पीछे जुटते हैं, जिनके पीछे जुटने से, वे सोचते हैं कि कुछ मिल सकेगा। इसलिये यह देखा जाता है कि जो पार्टी सरकारी गद्दीनशीन रहती है उस पार्टी के नेतृत्व में परिचालित यूनियन के पंडों के पीछे मजदूर लोग ज्यादा जुटते हैं। वजह यह है कि वे सोचते हैं कि इन नेताओं को पकड़ने से मालिक के पास उन नेताओं कि सुनवाई होगी, उनकी कुछ मांगें मंजूर हो सकेंगी। जब ट्रेड यूनियन आंदोलन की मूल बात यही हो जाती है तब उस ट्रेड यूनियन के जरिये मजदूरों का मुक्ति आन्दोलन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, बढ़ ही नहीं सकता। इस तरह के श्रमिक आन्दोलन के साथ मजदूरों के क्रान्तिकारी आन्दोलन, मुक्ति-आन्दोलन का कोई सम्बन्ध नहीं है। चाहे उसका झंडा हरा हो, सफेद हो या लाल ही हो। मजदूरों में हमेशा विक्षोभ पैदा करना या नेतृत्व करने वालों द्वारा मांगें मंजूर करवाने की क्षमता के बारे में हमेशा झूठा मौह पैदा करना ही ट्रेड यूनियन के नेताओं का काम हो जाता है तब समझना होगा कि वह पार्टी या नेतृत्व इंग्लेण्ड की लेबर पार्टी या अमेरिका की बड़ी-बड़ी यूनियनों की तरह ही उदारपंथी ट्रेड यूनियनवाद व अर्थवाद का शिकार है। आप लोग गौर कीजियेगा अमेरिका या इंग्लैण्ड की ये सब ट्रेड यूनियनें कभी-कभी बात-बात पर पूरे देश के कल-कारखानों में हड़ताल कराती हैं। उत्पादन रुद्ध कराती हैं। ये दरअसल देश में एकाधिकारी पूँजीपतियों का ही एक विरोधी अंश हैं। इन्हें भी एकाधिकारी पूँजीपति लोग ही कंट्रोल करते हैं। जैसे इंग्लैण्ड की लेबर पार्टी बिटिश साम्राज्यवादियों की पिछलग्गू है। वे जब हड़ताल द्वारा इंग्लैण्ड के पूरे जनजीवन को ठप्प कर देती हैं तब उस हड़ताल के पीछे आम मजदूर मतवाले हो कर दौड़ते हैं। सोचते हैं अब शायद क्रान्ति शुरू कर दी है। पर इसके जरिये ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर आँच तक नहीं आती। बल्कि साम्राज्यवादी यह सोचकर धीमे-धीमे मुस्कराते रहते हैं कि यूनियन के धुरंधर नेताओं ने इस तरह के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में मजदूरों को बांध लिया है, फँसा लिया है और फँसे हुये मजदूर बंधी हुई गाय की तरह समझ भी नहीं पाते कि नेताओं की शैतानी चालों से वे बंधे गये हैं। इसलिये मार्क्स, लेनिन ने बार-बार यह चेतावनी दी कि ट्रेड यूनियनें साम्यवाद के स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि हजारों-हजार मजदूर जो रोजमर्रे के सवालों को लेकर संघर्ष के लिए एकजुट होते हैं उन्हें सिर्फ तालियाँ बटोरने के ख्याल से बेतुकी जोशीली बातें कहकर मत भड़काओ। जिस दुश्मन को पहचानते हो उसके आगे पीछे दस अलंकार जोड़कर भाषण देकर समय बर्बाद मत करो, कुछ काम की बातें कहो। यदि किसी आन्दोलन की सफलता की सम्भावना रहे तो उसकी असफलता के भी जितने पहलू रह सकते हैं उनके बारे में मजदूरों को सचेत करो। फिर किसी आन्दोलन के विफल होने पर भी वह क्यों विफल हुआ इसे समझाने के साथ-साथ इसकी विफलता के भीतर भी सफलता के पहलू हैं उनके बारे में मजदूरों को अवगत कराने का काम ही नेताओं का काम है।

लेकिन मजदूर आंदोलन में यह सब नहीं किया जाता। मजदूरों को यह नहीं बताया जाता, नहीं सिखाया जाता कि रोजमर्रा के सब आंदोलनों को आखिरकार कौन से राजनैतिक लक्ष्य की ओर ले जाना होगा एवं उसके लिये आंदोलनों को किस तरह परिचालित करना होगा। मजदूरों को केवल गरम-गरम भाषण पिलाया जाता है-'आप लोग मजबूत संगठन बनायें, क्रान्ति के लिए तैयार हो जायें, दुर्ग-किले बनायें, ऐसे किलों का निर्माण करें जहाँ कोई घुस नहीं सके।' बस फौरन मजदूर भी लाठी लेकर खड़े हो गये और कर डाली किले की तैयारी। ऐसा किला जहाँ कोई इन्सान अगर अच्छी बात भी कहने आये, यदि वह उनकी पार्टी या संगठन का न हो तो फिर उसे वह बात कहने का मौका ही नहीं दिया जाये।

आप जानते हैं पूरे देश में इसी तरह अनेकों 'लाल किले' तैयार हुए थे। जैसे कि किसी खास पार्टी या संगठन की जागीरदारी हो। वहाँ किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। मैं कहता हूँ कि यदि कोई कुछ अच्छी बात भी कहता हो चूँकि वह पार्टी का आदमी नहीं है, चूँकि यह हमारा किला है इसलिये उसे घुसने नहीं दूँगा, उसकी भली बातों पर भी ध्यान नहीं दूँगा, यह कैसी बात है? हो सकता था शायद वह चर्चा मुक्ति आन्दोलन के ही काम आती। लेकिन चूँकि किला खड़ा किया है इसलिये कान पर ताला लगाना क्या कोई काम की बात है? नेता कहते हैं कि हर स्तर पर किले बनाओ। क्या इसके मायने यह है कि बुद्धि भी प्रवेश न कर सके? इस सब का नतीजा क्या निकला? इसके जरिये अंधता बढ़ती है? अंधता की मनोवृत्ति फासीवादी है। वह पूँजीपतियों की मदद करती है। मेहनतकशों का आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन अज्ञानता का कारोबार नहीं करता युक्तिहीनता का कारोबार नहीं करता। वह युक्ति तर्क-वितर्क आपसी चर्चा व सैद्धान्तिक संघर्ष पर विश्वास करता है। क्योंकि वे सत्य की खोज करने वाले लोग हैं। आलोचना, तर्क-वितर्क से वे नहीं डरते हैं। सिर्फ वे ही आलोचना को दबाना, हतोत्साहित करना चाहते हैं जो गलत जगह पर हैं, जो प्रतिक्रियावादी हैं। इसलिए वे भी अनुशासन की दुहाई देकर, किले वगैरह तैयार करने की बातें करके असलियत में आपसी चर्चा को ही दबाना चाहते हैं। वे तर्क-वितर्क से डरते हैं, युक्ति, विचार-विश्लेषण से डरते हैं। जब वे किसी को भाषण में विश्लेषण करते देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं-'क्लास' ले रहा है। मानो केवल भड़काने के लिए ही भाषण देने की जरूरत है। फिर भले ही भड़काने के बाद लोग इधर-उधर छिट-पुट लड़ाई-भिड़ाई में मरें। मरते तो हैं आम लोग ही, नेता तो नहीं मरते। इन सब नेताओं में से कब कौन कहाँ गोली खाकर मरे हैं? ये नहीं मरते। कभी-कभी क्रान्तिकारी लोग मरते हैं, पर इन सब नेताओं को तो पुलिस सर-सर कह कर सिर पर उठाये रखती है। चारों ओर से अगोर कर रखती है। इसलिए ये नेता, लोगों को केवल भड़काते हैं। भड़कने पर जितने ज्यादा लोग मरते हैं उतना ही इन नेताओं के लिए अच्छा होता है। दो एक शहीद दिवस मनाकर, शासक पार्टी को गाली-गलौच कर इन नेताओं को चुनावी वैतरणी पार करने का मौका मिल जाता है।

सही राजनैतिक लाइन ही क्रान्ति की मुख्य शर्त है

मैं कहता हूँ कि क्रान्ति के लिए तो लोगों को मरना ही पड़ता है लेकिन इतनी लड़ाई, इतने मृत्युवरण के बाद भी प्रतिक्रियावादी कैसे ताकतवर हो रहे हैं? असली बात क्या है? असली बात है - सही रास्ता, सही क्रान्तिकारी सिद्धान्त और राजनीति की बात। जिस देश में लड़ रहे हैं उस देश की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था किस तरह की है, राजसत्ता का चरित्र किस तरह का है? इसे अच्छी तरह समझना जरूरी है। कुछ ही दिन हुए चीन की पार्टी ने अपनी दसवीं कांग्रेस में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही, जो मुझे पसन्द आयी। ऐसी एक पार्टी जिसने क्रान्ति की , उसके बाद सांस्कृतिक क्रान्ति की, जो एक इतने विशाल देश की कर्त्ता-धर्त्ता है, या हमारे पीछे इतनी कमेटियों का समर्थन है, इसलिए हम ठीक हैं। बजाय इसके वह कह रही है कि अगर रास्ता या मूल राजनैतिक लाइन ठीक न हो तो भले ही आज ताकत या जनसमर्थन रहे, फौज भी रहे, संगठन भी रहे, आखिर तक इन्हें रखा नहीं जा सकेगा। रास्ता गलत होने से धीरे-धीरे सब कुछ चला जायेगा। इस बात से यह मान लिया गया कि रास्ता गलत होने के बावजूद जब तक आम इन्सान अपने अनूभव के आधार पर पकड़ नहीं पाते कि गलती कहाँ है, तब तक गलत लाइन के पीछे भी जनसमर्थन रह सकता है। नहीं तो किस तरह हिटलर जर्मनी का एक अद्वितीय नेता बन गया था। किस तरह तानाशाह नासिर मिस्र के कर्ता-धर्ता नेता बने हुए हैं और कम्युनिस्टों का दमन कर रहे हैं। लाइन गलत होने पर भी लोकप्रियता अर्जित की जा सकती है एवं उसे कुछ समय तक कायम रखा जा सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन के समय तक मुस्लिम किसान मजदूर मध्यम वर्ग पर मुस्लिम लीग के प्रभाव में मिलता है। लेकिन क्या इस समर्थन को ज्यादा दिन तक कायम रखा जा सका? नहीं। इसलिए चीन की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी इतने कार्यकर्ता व जनसमर्थन रहने के बावजूद कह रही है कि यदि एक आदमी से ही पार्टी बनना शुरू होती है -रास्ता ठीक रहने से एक से दो होंगे, दो से पाँच होंगे इस तरह राजनैतिक शक्ति का जन्म होगा और वह पार्टी सत्ता पर कब्जा करेगी। इसलिए रास्ते का ठीक होना एक मुख्य शर्त है। मार्क्स, लेनिन सभी ने इस बात पर जोर दिया है-कहे हैं अलग-अलग भाषा में। मार्क्स ने कहा -जो सर्वहारा हैं दुनिया को केवल वे ही बदल सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले द्वन्द्वात्मक वस्तुवाद के सहारे दुनिया को बदलने का विज्ञान संगत रास्ता खोजा - कहा, मजदूर दुनिया को बदल सकते हैं। इस बात का मायने यह नहीं की कि मजदूर सिर्फ इसलिये कि वे सर्वहारा हैं दुनिया को बदल सकते हैं। जिस किसी भी तरीके से, हजारों-हजार सर्वहारा मजदूर संगठित होकर, क्रान्ति के नारे लगाने से ही क्या वे दुनिया बदल सकेंगे? नहीं। यह केवल उनके द्वारा ही सम्भव है जिन्होंने पहले अपने को बदल कर क्रान्ति के लायक बना लिये हो।

(शेष अगले अंक में)

जन समस्याओं के समाधान हेतु सौंपा ज्ञापन

जमशेदपुर (झारखण्ड) : 10 जून को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) जमशेदपुर नगर कमिटी की ओर से उपायुक्त (पूर्वी सिंहभूम) कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के उपरांत एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त महोदय से भेंट कर निम्नोक्त ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है। यहां के लोगों ने उद्योगों को फूलने-फलने के लिए वर्षों से ईमानदारीपूर्वक मेहनत की है। अब उद्योगों से लोगों को निकाला जा रहा है। ठेकेदार मजदूरों का जबरदस्त शोषण जारी है। टायो कंपनी बंद कर हजारों लोगों को सड़क पर लाने की तैयारी चल रही है।

जमशेदपुर में प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता-समर्थक

इसके साथ ही जमशेदपुर, विशेषकर मानगो के लोग न्यूनतम नागरिक अधिकारों से भी वंचित हैं। नलों में कभी कभार पानी सप्लाई होती है तो उसमें कीड़े-मकौड़े तैरते हुए मिलते हैं। दिन के 10 बजे के बाद मानगो ब्रिज से पार होना असंभव सा लगता है। बिजली आपूर्ति की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है। अपराध बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण शराब है। शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही है। टायो कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाने, स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति की जाने, निर्बाध व नियमित बिजली आपूर्ति की जाने, जमशेदपुर में दिन के समय नो एंट्री लागू की जाने और पूर्ण शराबबंदी लागू की जाने की उपायुक्त महोदय से मांग की गयी।

कार्यक्रम में जिला सचिव कॉमरेड बिमल दास के अलावा कॉमरेड्स सुमित राय, पतित पावन कुईला, जयंत सोलंकी, मुकुल मिश्रा, गोपाल कुमार, सोहत महतो, प्रवीण कुमार, रिंकी बंसरियार, अजय राय, संदीप पात्रो, अरूण सिंह, सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।

महिला संगठन ने लगाया शिक्षण शिविर

गुना (म.प्र.) : ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की मध्य प्रदेश राज्य समिति के द्वारा दो दिवसीय शिक्षण शिविर गुना में आयेजित किया गया। इसका संचालन एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल ने किया।

शिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को शरतचन्द्र के द्वारा लिखित उपन्यास 'ब्राह्मण की बेटी' और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एक मार्क्सवादी मुल्यांकन' पढ़ने के लिए कहा गया था। सभी साथियों ने दोनो पुस्तकों पर जीवन्त चर्चा में भाग लिया। राज्य की अलग-अलग जिलों की नेत्रियों ने सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, साथ ही आगामी 28-29 अगस्त 2016 को होने वाले राज्य सम्मेलन की विस्तारित चर्चा की। सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने महिलाओं एवं बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की और म.प्र. में इसके खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करने का संकल्प लिया।

इस शिविर में संगठन की भोपाल, जबलपुर, सागर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, अलीराजपुर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, इंदौर, बैतुक आदि जिलों की कार्यकर्ता शामिल हुई।

गुना

किसानों ने की लिफ्ट नहर चालू करने की मांग

नरवर जिला शिवपुरी : 7 जून को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में दो साल से बंद पड़ी लिफ्ट नहर को दोबारा चालू किये जाने की मांग को लेकर किसान मंगरोनी गांव में एकत्रित हुए और तहसील कार्यालय पहुंच कर एक प्रदर्शन किया जिसमें किसानों ने अपनी मांगों के नारे लगाये। प्रदर्शन में मंगरोनी, देवरी, देवरा, दौलताबाद ठाठी और कैखो मिलाकर 6 गांवों के करीब सौ किसान शामिल हुए।

प्रदर्शन को पूर्व सरपंच सरमन सिंह कंषाणा, रामकरन सिंह जाट, जयकरन सिंह, ख्यालीराम वघेल, पंजाब सिंह राव, सरदार विचित्र सिंह आदि ने सम्बोधित किया। प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए ऑल इण्डिया केकेएमएस के राज्य सचिव कॉ. मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि नहर को जल्द शुरू करवाने के लिए संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने किसानों की अन्य-अन्य समस्याओं पर भी जोरदार आन्दोलन खड़ा करने की अपील की। प्रदर्शन में डाक्टर चन्द्रेश, बेताल सिंह, राजू, सुल्तान, अंग्रेज सिंह, राजकुमार आदि किसान नेता भी शामिल हुए।

राजस्थान में स्टडी क्लास

जयपुर : एसयूसीआई(सी) राजस्थान राज्य सांगठनिक कमेटी के तत्वावधान में 28 मई को स्टडी क्लास आयोजित हुई। सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की 'गांधीवाद : एक आलोचनात्मक अध्ययन' नामक पुस्तक को लेकर कॉमरेडों की आपसी चर्चा-बहस के अंत में समग्र विषय को लेकर विस्तार से चर्चा केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने की।

हरियाणा में विचारगोष्ठियों में हुई बेरोजगारी पर चर्चा

भिवानी (हरियाणा) : बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ 11 जून को एआईडीवाईओ की तरफ से चेतराम प्रजापति धर्मशाला स्थित संगठन के जिला कार्यालय में एक विचार गोष्ठी की गई। इसकी अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष कॉ. विकास ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. रामफल रहे। सभा का संचालन डी.वाई.ओ. के जिला सचिव कॉ. सन्दीप मेहरा ने किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. रामफल ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। रोजगार की तलाश कर रहे करोड़ों बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन केन्द्र व राज्य की जनविरोधी नीतियों के चलते रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। छिपी हुई बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी व्याप्त है। 'कौशल विकास योजना' जैसी भ्रामक योजनाओं द्वारा पढ़े लिखे एवं कुशल युवाओं का मजाक बनाया जा रहा है। रोजगार का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार होना चाहिए। सरकार द्वारा जहां एक तरफ जनसंख्या ज्यादा होने का गलत पाठ पढ़ाकर नौजवानों को भ्रमित किया जाता है, स्वरोजगार का झांसा दिया जा रहा है और आरक्षण के नाम पर लड़ाकर उनकी एकता तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि आरक्षण मिलने पर भी नौकरी मिलने की कोई गारन्टी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ शराब, नशा, सैक्स, हिंसा और अश्लीलता परोस कर लोगों, खासकर नौजवानों की नैतिक रीढ़ को तोड़ डालने की साजिश जारी है। उन्होंने पूँजीपतियों की ताबेदार भाजपा सरकार की रोजगार विरोधी-नीतियों के खिलाफ जोरदार युवा-आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत पर बल दिया।

भिवानी

सभा में राजकुमार, कमल, राजेश, विशाल, कुलदीप, मुकेश, ममता, प्रेम, जयबीर, पूजा, पवन आदि अनेक युवक-युवतियां शामिल हुए।

रेवाड़ी में सब को रोजगार की मांग को लेकर डीवाईओ की ओर से 29 मई को स्थानीय नेहरू पार्क में सम्मेलन किया गया। इसमें संगठन के जिला सचिव कॉ. अनिल कुमार, अजय कुमार, करतार सिंह, राम, राजेश, अमरदेव, पवन कुमार, पोहप सिंह, वेदप्रकाश आदि भी मौजूद रहे। सरकारी विभागों में खाली पड़े पद शीघ्र भरने, नई भर्तियों पर लगी रोक हटाने, नव चयनित जेबीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र देने, नौकरियों में भाई-भतीजावाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार व राजनैतिक हस्तक्षेप बंद करने, नौकरी के लिए आवेदन फीस व परीक्षा फीस समाप्त करने आदि की मांग की गई। सम्मेलन के मुख्य वक्ता एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. राजेन्द्र सिंह थे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की जननी यह शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था है। युवा आन्दोलन की दिशा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ होनी चाहिए।

महेन्द्रगढ़ जिला में भी गत दिनों बेरोजगारी की समस्या पर डीवाईओ की ओर से कन्वेन्शन किया गया। इसका संचालन डीवाईओ के कॉ. सतीश कुमार ने किया और मुख्य वक्ता डीवाईओ के राज्य संयोजक कॉ. सुमेर सिंह थे। कन्वेन्शन में कम्प्यूटर लैब सहायक संघ के जिला प्रधान रोहताश, कनीना ब्लाक प्रधान कमलेश, महेन्द्रगढ़ ब्लाक प्रधान अति यादव, नरेन्द्र, संदीप, राजेन्द्र, सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभी को रोजगार देने और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक जीने लायक बेरोजगारी भत्ता देने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, खाली पड़े सभी पद भरने आदि की पुरजोर मांग की गई।

हरियाणा में बुढ़ापा पेन्शन पर लगाई नाजायज शर्तें वापस ले सरकार

– एसयूसीआई(सी)

रोहतक (हरियाणा) : हरियाणा में भाजपा की खट्टर सरकार द्वारा बुजुर्गों को मिलने वाली बुढ़ापा पेन्शन पर तरह-तरह के अंकुश लगाये जाने का एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड सत्यवान ने 8 जून को जारी एक बयान में कड़ा विरोध किया है। बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा की खट्टर सरकार ने तरह-तरह के बहाने बनाकर बुढ़ापा पेंशन में कांट-छांट करने का जो फैसला किया है वह सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाला एक जनविरोधी व अन्यायपूर्ण कदम है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि भयंकर रूप से बढ़ती महंगाई के इस दौर में बुढ़ापा पैन्शन सरकार कम से कम 5000 रुपये दे। छात्र-युवाओं, सुबुद्धिसम्पन्न नेक ख्याल के लोगों समेत प्रदेशवासियों से हम अपील करते हैं कि बुजुर्गों के मान-सम्मान और बुढ़ापे की लाचार-मजबूर अवस्था में काम आने वाली उनकी बुढ़ापा पैन्शन को बचाने के लिए पुरजोर आवाज उठायें।

सभी जानते हैं कि विधान सभा चुनावों से पहले भाजपा ने बुढ़ापा पेन्शन 2000 रु महीना देने का वादा किया था। परन्तु सत्ता में आते ही खट्टर-सरकार इससे मुकर गई। लोग ठगे से देखते रह गये। अब इसने ताजा फरमान जारी किया है कि ऐसे बुजुर्ग बुढ़ापा पेन्शन के हकदार नहीं रहेंगे जिनके घर में 165 लीटर से बड़ा फ्रिज है या चार पहिया वाहन है–कार, जीप, टैक्टर आदि है। ऐसा बुजुर्ग जो पेन्शन लेना छोड़ देगा उसे सरकार सोने के रंग में छपा हुआ प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित करेगी। साथ ही यह भी फरमान है कि ऐसा बुजुर्ग यदि अगस्त 2016 तक पेन्शन लेना बन्द नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जायेगी। बुढ़ापा पेन्शन के अपात्र ऐसे लोगों को पकड़वाने की सूचना देने वाले को सरकार 5000 रुपये ईनाम देगी, जैसे किसी शातिर अपराधी को पकड़वाने के लिए देती है; पकड़वाने की सूचना देने वाले की पहचान को सरकार गुप्त रखेगी। सरकार ने यह भी कहा कि जिस बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण अर्थात् उनकी सेवा-पानी, देखरेख, दवाई-इलाज पर यदि उनके बच्चे खर्चा न करें तो वे एस.डी.एम. की अदालत में दावा डाल सकते हैं। सरकार उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये तक का खर्चा दिलायेगी। सरकार कह रही है कि इसके लिए एक भरण-पोषण कानून (मेन्टीनैन्स एक्ट) बना हुआ है।

सरकार का यह कहना है कि हर साल बुढ़ापा पेन्शन लेने वालों की संख्या बढ़ने से सरकारी खजाने पर खर्च का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को हल्का करने के लिए ही सरकार ने बुजुर्गों की पेन्शन में कटौती करने की यह तरकीब निकाली है। जबकि केन्द्र व प्रदेश की सत्ता में बैठी ये ही सरकारें खुद अपने ऊपर और बड़े-बड़े पूँजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए अरबों-खरबों रुपये सरकारी खजाने से लुटाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती हैं। सवाल उठाता है कि इस सरकारी खजाने में जमा जनता के धन में मध्यम, निम्न मध्यम व गरीब तबके का क्या कोई साझा या हिस्सा-पत्ता है या नहीं?

यह जग-जाहिर है कि मुख्यमन्त्री से लेकर मन्त्री व विधायकों आदि तक, सभी के लिए गाड़ी, मकान, भोजन, टेलिफोन, बस-रेल-हवाई यात्रा सब कुछ मुफ्त-फ्री है। ऊपर से हर महीने मनमानी मोटी तन्खाह-वेतन-भत्ते हैं और पाँच साल पूरे होने पर पर्याप्त पेन्शन है। क्या खट्टर सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने पूर्व-मुख्यमन्त्री, पूर्व-मन्त्री या पूर्व-विधायक हैं जिन्होंने पेन्शन लेना छोड़ दिया है। क्योंकि इनमें से शायद ही कोई होगा जिसके परिवार की आमदनी 20 हजार रुपये से कम हो। बात-बात पर बेमतलब की तकरार करने और बाल की खाल निकालने वाले और जनसेवक कहलाने वाले ये माननीय नेतागण अपने वेतन, भत्ते, पेन्शन बढ़ाने में एक क्षण की भी देर नहीं लगाते हैं। ऐसे में, खट्टर सरकार को बुजुर्गों के 1400 रुपये महीना अखरने का आखिर औचित्य क्या है? ऊपर से वह बुजुर्गों को एस.डी.एम. की अदालत में धक्के खाने का रास्ता दिख रही है। वेद-शास्त्र-गीता की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार को यह ज्ञान कहाँ से मिला है?

एस.यू.सी.आई(कम्युनिस्ट) का सुनिश्चित मत है कि बुढ़ापा पेन्शन कोई खैरात, भीख या प्रसाद नहीं है जो सरकार दे या नहीं दे। यह बुजुर्गों का बुनियादी हक है। 60 साल की उम्र होने तक जो अपनी कड़ी मेहनत से खेत, खलिहान, खान-खदान या कल-कारखानों आदि में जहाँ-तहाँ उत्पादन-पैदावार में भागीदारी करते हैं, देश की धन-दौलत बढ़ाते हैं, समाज को भोजन, कपड़ा, मकान पैदा करके देते हैं, मरते दम तक काम में लगे रहते हैं, क्या बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का कोई हक नहीं है? हमारी पक्की राय है कि जिस तरह से पुलिस-फौज या अन्य सरकारी सेवाओं में अनिवार्य पेन्शन का प्रावधान है उसी तरह से गैरसरकारी कार्य (कृषि, मजदूरी व घरेलू कार्यों समेत) करने वाले हर नागरिक का भी पेन्शन प्राप्त करने का हक बनता है। बुढ़ापा सब में आता है। पहले पहल समाजवादी देशों में हर बुजुर्ग को पर्याप्त बुढ़ापा पेन्शन का यह हक दिया गया था। फिर यूरोप के देशों को भी इसे मान्यता देनी पड़ी। आजादी के 70 साल बाद भी अपने इस महान भारत के बुजुर्गों के साथ ऐसी बदसलूकी करना अत्यन्त खेद व रोष की बात है। कॉमरेड सत्यवान ने मांग की कि खट्टर सरकार इस काले फरमान को वापस ले अन्यथा आन्दोलन जारी रहेगा।

बढ़ती बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के खिलाफ एआईडीवाईओ का प्रथम जिला सम्मेलन सम्पन्न

मुजफ्फरपुर (बिहार) : 10 अप्रेल को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम जिला सम्मेलन शहर के स्थानीय डा. राम मनोहर लोहिया स्मारक विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन युवाओं के जीवन की ज्वलन्त समस्यायों बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आन्दोलन तेज करने के लिए आयोजित हुआ।

सम्मेलन की शुरूआत संगठन के मार्गदर्शक इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉ. शिवदास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। माल्यार्पण करने वालों में एस.यू.सी.आई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार, युवा संगठन एआईडीवाईओ की राष्ट्रीय महासचिव कॉ प्रतिभा नायक, युवा संगठन के राज्य प्रभारी कॉ. ज्योति कुमार समेत संगठन के राज्य कमेटी सदस्य थे।

सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर संगठन की राष्ट्रीय महासचिव कॉ. प्रतिभा नायक ने कहा कि आज देश में विकराल होती बेरोजगारी की समस्या नौजवानों की जिन्दगी को तबाह कर रही है। आज नौजवानों को देश के महान सपूतों भगत सिंह, सुभाषचन्द्र बोस, खुदीराम बोस, गुल्बा साहनी, बैकुंठ शुक्ल के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर उनके विचारों से लैस होकर सशक्त जुझारू, जोरदार युवा आन्दोलन तेज करने की जरूरत है। यह काम समाज में उन्नत स्तर का वैकल्पिक सांस्कृतिक माहौल कायम करने पर ही संभव होगा। उन्होंने 22 से 25 नवम्बर तक पटना में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय युवा सम्मेलन को शानदार ढंग से सफल बनाने की अपील की।

इसके बाद मूल राजनैतिक प्रस्ताव व सांगठनिक रिपोर्ट पेश किया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव तकनीकी क्षेत्र के इंजिनियरिंग संस्थानों, आई.आई.टी., आई.टी.आई. संस्थानों में की जा रही बेतहाशा फीस वृद्धि के खिलाफ, आई.टी.आई कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के खिलाफ व आई.टी.आई., पॉलिटेकनिक कॉलेजों के छात्रावासों की जर्जर स्थिति के खिलाफ एवं छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने के लिए, देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला व असहिस्णुता के खिलाफ पेश किया गया। तीसरा प्रस्ताव महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ आन्दोलन तेज करने का पेश किया गया। इनको ध्वनिमत से पारित किया गया।

सम्मेलन के मुख्य वक्ता एस.यू.सी.आई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार ने कहा कि हर युग में सामाजिक विकास व परिवर्तन के लिए चलने वाले आज क्रान्तिकारी संघर्षो में युवाओं की अग्रिम भूमिका रही है। आज हमारे देश में काफी भयानक परिस्थिति पैदा हो चुकी है। जिस लोकतंत्र ने देश के नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार दिया, उसी देश में विचारों में मतभेद होने पर देश के तार्किक मानसिकता वाले बुद्धिजीवियों यथा दाभोलकर जैसे लोगों की हत्या तक की जा रही है। हमारे समाज में महिलायें, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, अश्लीलता को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके खिलाफ युवा समाज को आगे आना होगा। सिर्फ सरकारों की अदला-बदली से युवाओं की समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। देश की युवाओं की समस्याओं का सम्बन्ध वर्तमान सामाजिक समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। देश की मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था घोर संकट के दौर में है। और इसी कारण से यह व्यवस्था समाज को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में असमर्थ है। इसलिए युवाओं को अपने जीवन की समस्याओं के हल के लिए पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ चल रहे सामाजिक संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लेकर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का तेज करते हुए इस पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर शोषणविहीन समाजवादी व्यवस्था कायम करनी होगी।

अंत में जिला की नवनिर्वाचित जिला कमेटी का गठन किया गया। इसके सचिव लालबाबू राम, अध्यक्ष अरविन्द कुमार, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार, उपाध्यक्ष के रूप में कुमुदराम, उमेश राम, उदय झा, सचिव मण्डल सदस्य के रूप में समसेवक विश्वभूषण, देवेन्द्र मांझी, जाहिद आलम, कार्यकारिणी सदस्य, मो. मजीद, डा. टी.एन. सिंह, रंजीत कुमार, मोहन राय, अमोद कुमार, बिरजू कुमार समेत 28 सदस्यीय जिला काउंसिल का गठन किया। कार्यक्रम का समापन इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार कॉ. शिवदास घोष पर रचित गान से हुआ।

महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ कन्वेन्शन

बैतूल (मध्य प्रदेश) : महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से यहां सारणी क्षेत्र में 3 जून 2016 को स्थानीय कन्वेन्शन किया गया। सभा की शुरूआत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई जिसमें स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया। सभा को सम्बोधित करते हुए कार्यक्रम की मुख्य वक्ता संगठन की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी सदस्या कॉमरेड जॉली सरकार ने कहा कि यह कन्वेन्शन आज हम ऐसे हालातों में कर रहे हैं जब महिलाओं और बच्चियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या तथा बलात्कार जैसी घटनाएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। बैतूल जिला भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं हैं। यहाँ कुछ महीने पहले करीब 11 आदिवासी युवतियों को एक युवक द्वारा नौकरी का झाँसा देकर ले जाया गया और उन्हें बेच दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के अन्याय-अत्याचार को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उच्च नीति-नैतिकता और संस्कृति पर आधारित आंदोलन गठित करना।

कार्यक्रम में राज्य कमेटी सदस्या कॉमरेड आभा भुवनकर ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में कॉमरेड आशा चौहान द्वारा एक प्रस्ताव भी रखा गया जिसके समर्थन में स्थानीय महिलाओं जया राठी, नीलू गुप्ता, नर्गिस सिद्दीकी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन कॉमरेड छवि पवार द्वारा किया गया।

पटना में संयुक्त श्रमिक सम्मेलन

पटना : आईएमए हॉल में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए कॉ. अरुण कुमार सिंह

11 जून को पटना के आईएमए हॉल में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आगामी 2 सितंबर, 2016 को घोषित अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल करने के उद्देश्य से एक कन्वेन्शन आयोजित की गयी। कन्वेन्शन का संचालन केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं को लेकर गठित अध्यक्ष मंडली ने किया। इस अध्यक्ष मंडल में इंटक के चंद्रप्रकाश सिंह, एटक के गजनफर नवाब, सीटू के राजकुमार झा, एआईयूटीयूसी के अरूण कुमार सिंह, एक्टू के आर.एन. ठाकुर तथा एएमयू के श्यामलाल किशोर शामिल थे।

कन्वेन्शन को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के केन्द्रीय कमिटी कार्यकारणी सदस्य कॉ० बिमल जाना ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमले किये जा रहे हैं। असंगठित मजदूरों की हालत और भी दयनीय है। उनके लिए सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा कानून न के बराबर है, जो है भी वह काफी ढीला-ढाला। उन्होंने आगे कहा कि जिन कार्यक्षेत्रों में सालों साल काम होता है, वहाँ भी ठेकाकरण किया जा रहा है। समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है। सरकारी योजनाओं में काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाना चाहिए। जैसे- आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, मध्याह्न भोजन कर्मी, आशा कर्मी आदि। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 18000 रुपये होनी चाहिए और वृद्धावस्था में काम छूट जाने के बाद पेन्शन आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि सरकार यूनियन बनाने के अधिकार पर भी हमला कर रही है। ऐसा क्यों? दरअसल सरकार मालिक पूंजीपति वर्ग के लिए खुलकर काम करना चाहती है। मजदूरों का यूनियन रहने से यह छूट नहीं मिल पायेगी। इसलिए सरकार यूनियन से डरती है। उन्होंने आगामी 9 अगस्त के आंदोलन और 2 सितंबर की हड़ताल को जोरदार ढंग से सफल करने की अपील की।

वहीं कन्वेन्शन को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य अध्यक्ष और कन्वेन्शन के अध्यक्ष मंडल सदस्य कॉ० अरूण कुमार सिंह ने कहा कि तमाम मजदूरों का संगठन एक होना चाहिए था, क्योंकि सारे मजदूरों का स्वार्थ एक है। मजदूरों की यूनिटी बिखरी हुई है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि सरकारों की अदला बदली से मजदूरों को पूंजीवादी शोषण से मुक्ति नहीं मिलेगी। पूंजीवादी राजसत्ता रूपी दमनकारी मशीन को मजदूरों की संगठित ताकत से ध्वस्त कर देना होगा। इसके लिए लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल चलाते हुए इसे पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति में तब्दील कर देना होगा।

कन्वेन्शन में दो प्रस्ताव लाए गए। पहला, पटना आर्ट एण्ड क्राफ्ट कॉलेज में प्राचार्य की बर्खास्तगी और निलंबित छात्रों की पूर्ण बहाली आदि की मांगों पर चल रहे छात्र आंदोलन से संबंधित तथा दूसरा आगामी 11 जुलाई को होने वाली रेल हड़ताल। इन दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये और इसके समर्थन में उतरने का फैसला लिया गया। अन्य वक्ताओं में इंटक के चंद्रप्रकाश सिंह, एटक के राजेन्द्र प्रसाद सिंह व चक्रधर प्रसाद सिंह, सीटू के गणेश शंकर सिंह, एक्टू के आर.एन. ठाकुर तथा एएमयू के नृपेण कृष्ण महतो आदि शामिल थे।

हरियाणा में पायनियरों का समर कैम्प

सोनीपत : 3 और 4 जून को हरियाणा के सोनीपत शहर में पार्टी से जुड़े परिवारों के 60 बच्चों-किशोरों को लेकर पायनियर समर कैम्प आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य व हरियाणा राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड सत्यवान ने किया। एआईडीएसओ की अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य कॉ. चंचल घोष ने विज्ञान के विभिन्न प्रयोग करके दिखाये। मनीषियों, शहीदों और वैज्ञानिकों की जीवनी को लेकर चर्चा, कहानी, गाने आदि के कार्यक्रम में भी किशोरों ने भागीदारी की। कई खेलकूद, व्यायाम और परेड भी हुई।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के खिलाफ हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 जून को प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(सी) के कार्यकर्ता।

एआईडीवाईओ द्वारा प्रदर्शन

सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) : झारखण्ड राज्य के सरायकेला-खरसावाँ जिला के चाण्डिल प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष विभिन्न जन समस्याओं को लेकर एआईडीवाईओ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। चांडिल के चैनपुर गांव स्थित कैनाल से प्रखंड विकास कार्यालय तक एक सुसज्जित रैली निकाली गई। इसमें प्रखंड के विभिन्न गांव से सैकड़ों की संख्या में युवकों व आम लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में संगठन के जिला उपाध्यक्ष गौतम महातो, जिला सचिव सुशांत सरकार, प्रखंड अध्यक्ष भुजंग मछुआ, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र गौड़, सचिव रंजित कुमार, मानो सिंह सरदार, पंचु मांझी आदि भी उपस्थित थे।

दुर्घटना में मारे गये श्रमिकों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की यूनियन ने की मांग

नारनौल (हरियाणा) : 5 जून को एआईयूटीयूसी सम्बन्धित भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा की महेन्द्रगढ़ जिला कमेटी की बैठक जिला प्रधान कॉ. सीताराम की अध्यक्षता में शहर के सुभाष पार्क में हुई। बैठक में 3 दिन पूर्व पुल बाजार में दुकान का निर्माण करते समय पड़ोस की दुकान का छज्जा गिरने से अकाल मौत का शिकार हुए 3 मिस्त्री-मजदूरों की याद में 2 मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजली दी। प्रधान कॉ. सीताराम ने कहा कि सुरक्षा मानकों में खामियों के चलते महेन्द्रगढ़ जिले में आये दिन निर्माणाधीन मकान गिरने से दर्दनाक हादसे हा रहे हैं। मृतकों के आश्रितों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की उन्होंने मांग की। यूनियन के राज्य कार्यालय सचिव कॉ. जगदीश चन्द्र ने कहा कि भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा मिलने वाले हितलाभ समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये।

मजदूरों ने सुभाष पार्क से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन कर मजदूरों की समस्याओं के सन्दर्भ में श्रम मंत्री हरियाणा सरकार के नाम 10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन तहसीलदार ईश्वर सिंह को सौंपा।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7-8 and 22-23 Fortnightly , Date of Publication :20 June, 2016
सर्वहारा दृष्टिकोण
22 जून, 2016

कांग्रेस – बीजेपी ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

सरकार की जनविरोधी नीतियां आम आदमी को तबाही के कगार पर धकेल रही हैं। बीजेपी कह रही है कि भारत को कांग्रेसमुक्त करना होगा और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपीमुक्त करना होगा। हम कह रहे हैं कि भारत को साम्प्रदायिकतामुक्त करना होगा और जनविरोधी आर्थिक नीति का अनुसरण जिसमें नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जनता के सामने राजनैतिक विकल्प पेश करना होगा और सिर्फ वामपंथी दल ही यह विकल्प पेश कर सकते हैं।

सीपीआई के महासचिव कॉमरेड सुधाकर रेड्डी ने इस दिन के जुलूस को 'ऐतिहासिक' करार देते हुए कहा कि राज्य में सत्तासीन सिद्धारमैया सरकार के तीन साल के कुशासन और केन्द्र में सत्ता में बैठी मोदी सरकार के 'अच्छे दिन' लाने के झांसे के खिलाफ जनता का विक्षोभ इस जुलूस में फूट पड़ा है। सभी चीजों की महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। पेट्रोल-डीजल के दाम बार-बार बढ़ाये गये हैं। स्वच्छ भारत सैस या टैक्स लोगों पर थोप दिया गया है। दूसरी तरफ कारपोरेट टैक्स 5 प्रतिशत घटाया गया है। इसका मायने है, 12 हजार 600 करोड़ रुपये टैक्स माफी पूंजीपतियों को दी गई है। उधर 53 करोड़ आम आदमी घोर सूखे की चपेट में हैं। उनके लिए खर्चने को एक पैसा भी बजट में नहीं रखा गया है।

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने कहा कि पूंजीवादी शोषण से न केवल गरीब किसान-मजदूरों का जीवन ही असहनीय हो गया है, बल्कि पढ़े-लिखे मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत भी अच्छी नहीं है। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ आन्दोलन के सिवा और कोई वैकल्पिक रास्ता लोगों के सामने खुला नहीं है। इस आन्दोलन को बैंगलोर के कपड़ा कारखानों के मजदूरों की तरह ही मजबूत होना पड़ेगा। दिल्ली में 'निर्भया' काण्ड के प्रतिवाद में जिस तरह आन्दोलन हुआ था, सारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन ने जिस तरह व्यापक रूप लिया था, अन्तराष्ट्रीय स्तर पर 'अरब स्प्रिंग' आन्दोलन या वाल स्ट्रीट दखल करो आन्दोलन की तरह आन्दोलन हमें निर्मित करना होगा।

लेनिन ने कहा था कि क्रान्तिकारी सिद्धांत और क्रान्तिकारी पार्टी के बिना क्रान्ति नहीं होगी। इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की सही राजनैतिक लाइन तय नहीं कर पाने से मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। आज दुश्मन पूंजीवादी व्यवस्था है, जो राजनैतिक तौर पर न केवल मरणासन्न हो चुकी है, बल्कि आर्थिक, नैतिक और मूल्यबोध के पहलू से भी क्षयोन्मुख हो चुकी है। विश्व पूंजीवाद न हल होने वाले संकट से ग्रस्त है। निठल्ली पूंजी को निवेश करने के लिए पूंजीपति खाक छानते फिर रहे हैं। इसका नतीजा होगा अति-उत्पादन, बिक्री के बाजार पाने के लिए बढ़ेगी सामरिक तत्परता, छिड़ेगा युद्ध। उत्पादन आज युद्ध के साथ जुड़ गया है। साम्राज्यवादी मुँह से आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन वे ही आतंकवाद के जनक और मददगार हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम कहते हैं जनता की राजनीति। उसका एक ही मायने है – मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी नेतृत्व को सामने आकर क्रान्ति की अगुआई करनी होगी, जैसे रूस, चीन में की थी। आज बुर्जुआ वर्ग धर्म-वर्ण-जातपात, इलाकापरस्ती, प्रादेशिकतावाद, उग्रवाद आदि से जनता में फूट डाल रहा है। एकता को तोड़ रहा है। वे गली-सड़ी संस्कृति परोस रहे हैं। इसके उलट कम्युनिस्टों को ही सामूहिकता या कलैक्टीविज्म पर आधरित सबसे उन्नत संस्कृति को वहन करना होगा।

सीपीआई(एमएल)-लिबरेशन के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड स्वप्न मुखर्जी ने कहा कि इतिहास रचा जाता है राजपथ पर ही, न्याय के लिए संघर्ष में। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ रहे हैं अम्बानी, अडाणी, माल्याओं के। लेकिन आम आदमी मजदूर किसान छात्र नौजवान के लिए बड़े बुरे दिन हैं। वाम एकता को महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि समझौतापरस्त ताकतों के साथ वाम दलों को एका नहीं करना चाहिए।

सर्वभारतीय नेताओं के अलावा एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव कॉमरेड के. राधाकृष्ण सहित पाँचों पार्टियों के राज्य स्तरीय नेताओं ने भी बात रखी। वाम एकता जिन्दाबाद का नारा गूंज उठा फ्रिडम पार्क के मंच से। इस जुलूस और जनसभा ने जनता के सामने नई दिशा पेश की है। सभा में सर्वसम्मति से आन्दोलन की मांगों का प्रस्ताव भी पारित हुआ।

बैंगलोर में छात्रों ने किया रोष प्रदर्शन

प्रबंधन के अड़ियल रुख के कारण प्राइवेट मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों की सीटों के बंटवारे में पैदा हुई जटिल परिस्थिति के खिलाफ एआईडीएसओ का रोष प्रदर्शन । बैंगलोर 1 जून।

अमूल दूध और पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ रोष प्रदर्शन

अहमदाबाद (गुजरात) : देश के विस्तृत क्षेत्र में सूखे की मार झेल रहे आम आदमी को कुछ राहत देने की बजाय सरकार ने उन पर महंगाई और टैक्सों में वृद्धि का बोझ डाल दिया है। दूध के दाम बढ़ा दिये हैं। पेट्रोल-डीजल के दाम बार-बार बढ़ाये जा रहे हैं। दूसरी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं। केन्द्र की बीजेपी सरकार ने 'किसान कल्याण' सैस, 'स्वच्छता सैस' थोप कर यह बोझ और भी असहनीय कर दिया है। इसके खिलाफ 7 जून को एसयूसीआई(सी) की गुजरात राज्य कमेटी ने अहमदाबाद में रोष प्रदर्शन किया। इसमें कई महिलाओं सहित कई लोग शामिल हुए।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C).
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503